

संक्षिप्त समाचार

संत प्रेमानंद महाराज की जान को खतरा, मिले जेड प्लस सुरक्षा

वृंदावन। विख्यात संत प्रेमानंद महाराज और उनका ‘राधा केलि कुंज आश्रम’ पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा और विवादों के केंद्र में है। दीक्षित साधक रसिक दुलारी शरण की सदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और आश्रम के बाहर बच्चों के परिजनों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संत प्रेमानंद महाराज को तत्काल ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने और आश्रम से जुड़े कई संवेदनशील बिंदुओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिनेश शर्मा फलाहारी ने आरोप लगाया है कि आश्रम के भीतर शिष्यों के बीच दो गुट बन चुके हैं, जिससे वहां की आंतरिक व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जमीनों की खरीद-फरोख्त करने वाले और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आश्रम की गतिविधियों में दखल दे रहे हैं।

जस्टिस नरीमन बोले- खतरे में लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ले संज्ञान

नई दिल्ली। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और वोटिंग के अधिकार को प्रभावित करने के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने भी भारत के निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश में ऐसा निर्वाचन आयोग नहीं हो सकता जो इस तरह से काम करे या अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का सही निर्वहन न करे। उन्होंने यह टिप्पणी वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान लाखों वैध मतदाताओं के नाम कटने और उन प्रशासनिक रिपोर्टों के मद्देनजर की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथी दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की अनदेखी कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

जेम ग्रेनाइट के मालिक पर नाबालिगों से रेप का 5वां केस दर्ज

चेन्नई। मशहूर जेम ग्रेनाइट रूप के 84 वर्षीय मालिक आर. वीरमणि की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने उद्योगपति के खिलाफ पांचवां अलग आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह नई प्राथमिकी चेन्नई निवासी एक पीड़िता की औपचारिक शिकायत के बाद दर्ज की गई है। इसी बीच, तिरुवनामलाई की एक अन्य महिला ने भी एसआईटी से संपर्क कर आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी और चेन्नई आई थी।

300 से ज्यादा सांसदों का मार्च

राहुल गांधी का सवाल-ईसी जवाब क्यों नहीं दे रहे-हिरासत में कार्यकर्ता

नई दिल्ली/ एजेंसी

राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची में कथित हेरफेर और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को 300 से अधिक विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला। विजय चौक से लेकर मध्य दिल्ली तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और प्रदर्शनों के जरिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जबकि आकाशवाणी भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में मौजूद

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस वहां से मीडियाकर्मियों को हटा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेता आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं। विपक्षी दलों के 300 से ज्यादा सांसदों और नेताओं ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया। इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कड़ा सवाल उठाते हुए लिखा कि ये नेता करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं, लेकिन सीईसी उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें रोक रही है और धमकियां दे रही है। उन्होंने आगे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश के संविधान और व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़



किया गया है, वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसके जिम्मेदार लोग बच नहीं पाएंगे। विपक्षी सांसदों के इस प्रस्तावित मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने विजय चौक, नीति आयोग और निर्वाचन सदन के आसपास सुरक्षा

के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। कई स्तरों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है ताकि मार्च को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके बावजूद, सांसद और विपक्षी नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ

लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुच्छा इंतजार कर रखी थी। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में घुसने की कोशिश की। विपक्ष के मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं को रोक लिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गईं। विरोध प्रदर्शन के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पुलिस बैरियर पर चढ़कर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस ने विपक्षी नेता को हिरासत में लिया। सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर बैठे गए। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

अखिलेश और अभिषेक बनर्जी हिरासत में...

विपक्ष के इस हाई-प्रोफाइल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को हिरासत में ले लिया है। नीति आयोग के दफ्तर के सामने सुरक्षाकर्मियों ने इंडी गटबन्धन के मार्च को पूरी तरह से रोक दिया था। बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर नेताओं ने ‘वोट चोर’ जैसे नारे लगाए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफजमकर रोष प्रकट किया। तमाम पाबंदियों के बावजूद विपक्षी दल अपनी मांगों पर डटे हुए है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता आकाशवाणी भवन के परिसर में दाखिल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र में लागू बीएनएसएस की धारा 163 (निषेधाज्ञा) का हवाला दिया और इलाका खाली करने का निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़ से नईदिल्ली के लिए एक और ट्रेन शुरू

हफ्ते में दो दिन चलेगी अंबिकापुर-निजामुद्दीन

नई दिल्ली। सरगुजा के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग आखिर पूरी हो गई। अंबिकापुर से नई दिल्ली यानी निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन अब सप्ताह में दो दिन मंगलवार और गुरुवार को होगा। साप्ताहिक फेरे की शुरुआत सांसद चिंतामणि महाराज ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने रेल मंत्री आश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। ट्रेन के फेरे बढ़ने से विद्यार्थियों, व्यवसायियों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगा। साथ ही दिल्ली के अलावा देश के दूसरे प्रमुख शहरों तक आने-जाने के लिए भी यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प



मिलेगा। सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि सरगुजा के लोगों को बेहतर रेल सुविधा और मजबूत कनेक्टिविटी देना उनकी प्राथमिकता है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का दूसरा साप्ताहिक फेरा सरगुजा में रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने लिए कई फैसले

छोटे मध्यम उद्योगों के लिए 10 हजार करोड़ का वित्तीय पैकेज

नई दिल्ली/ एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश की एमएसएमई कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड की स्थापना का बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद (गुजरात के मुख्यमंत्री



से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक) पर 25 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर बधाई और बधाई प्रस्ताव भी पारित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही जीडीपी के साथ लॉजिस्टिक्स की मांग करीब 10प्रतिशत

की दर से बढ़ रही है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक ‘मल्टीप्लायर फैक्टर’ है। इस मांग को पूरा करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईटीएलए की स्थापना की जा रही है। आईटीएलए देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, रिसर्च, प्रोजेक्ट अप्रेंटिस, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स की शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगी। कुछ साल पहले शुरू किए गए ‘पीएम गतिशील’ पोर्टल के आधार को आगे बढ़ाते हुए यह संस्था 10 से 30 साल बाद की जरूरतों का अध्ययन करेगी। उदाहरण के लिए- बताया कि देश में 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत देश में कितने नए रेलवे नेटवर्क, हाईवे, एयरपोर्ट, सी-पोर्ट और इनलैंड वॉटरवे की जरूरत होगी।

नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद कांकेर में बड़ी वारदात

लौह खदान की मशीनों में लगाई आग, ‘लाल सलाम’ लिखे मिले दो पर्चे

भानुप्रतापपुर। संवाददाता

क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है? यह सवाल एक बार फिर उठने लगा है। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 को ‘नक्सल मुक्त’ घोषित किए जाने के बाद कांकेर जिले में सामने आई एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोहार थाना क्षेत्र के ग्राम चेमल स्थित पुष्प स्टील लिमिटेड की लौह अयस्क खदान में अज्ञात तत्वों ने खड़ी मशीनों में आग लगा दी। घटना में तीन पोकलेन मशीनें जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं मौके से दो पर्चे भी मिले हैं, जिनमें खदान को नियमित रूप से संचालित करने और एक सप्ताह के भीतर मांगें मानने की बात लिखी गई है। पर्चों में ‘लाल सलाम’ भी लिखा हुआ है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक

इस घटना को नक्सली वारदात होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि बीती शाम खदान में काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर अपने-अपने स्थान और कैंप में लौट गए थे। आज सुबह जब मजदूर दोबारा काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खदान में खड़ी मशीनों में आग लगी हुई थी। आग की चपेट में आने से तीन पोकलेन मशीनें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। इसके बाद घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद लोहार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी शेर बहादुर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आग लगने की वजह और घटना में शामिल लोगों के बारे में सुराग तलाश रही है।



पुलिस आसपास के इलाके की भी जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात घटनास्थल से मिले दो पर्चे हैं। बताया जा रहा है कि पर्चों में खदान को नियमित रूप से संचालित करने और एक सप्ताह के भीतर मांगें मानने की बात लिखी गई है। साथ ही

पर्चों पर ‘लाल सलाम’ लिखा हुआ है।पर्चों की भाषा और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए वारदात की नक्सली गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन पर्चों के पीछे वास्तव में नक्सलियों का हाथ है या किसी अन्य

व्यक्ति अथवा समूह ने नक्सली संगठन के नाम और अंदाज का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि वर्ष 2026 में बस्तर को नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किए जाने के बाद नक्सली अंदाज में सामने आई यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कांकेर जिले में कुछ नक्सली अब भी पूरी तरह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनकी तलाश में पुलिस और सुरक्षा बल समय-समय पर अभियान चलाते रहते हैं। यही वजह है कि इस घटना के बाद पुलिस भी नक्सली गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन पर्चों के पीछे वास्तव में संभावना को भी खंगाला जा रहा है।

नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर रखा था हथियारों का खजीरा बरामद किए

दतेवाड़ा। जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारसूर थाना क्षेत्र के कोहकाबेड़ा-बुरदूम के बीच जंगल और पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के एक डेप का पता चला है। यहां से एके-47, ईसास राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार, बम और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक, आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर इलाके में सर्चिंग अभियान शुरू किया गया था। जिला बल, डीआरजी, बस्तर फ़र्टिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम 5 अक्टूबर से मंमना, बुरदूम, तोड़मा और कोहकाबेड़ा इलाके में एरिया डोमिनेशन कर रही थी। इसी दौरान 6 अक्टूबर की सुबह करीब 6-30 बजे टीम को जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डेप मिला।

प्राकृतिक रंगों और धान से सजी विशाल रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र, जिलेभर में युवाओं ने दिया विकसित भारत 2047 का संदेश

रंगोली में दिखा विकसित भारत का सपना, ‘वंदे भारत’ ने मोहा मन

बलरामपुर (जनता के गोठ) : सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘राष्ट्र सेवा के रंग’ कार्यक्रम के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय बलरामपुर के प्रांगण में जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विशाल रंगोली के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का आकर्षक चित्रण करते हुए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत की तस्वीर प्रस्तुत की।

आयोजन का मुख्य आकर्षण विकसित भारत की परिकल्पना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के सेवा, संकल्प एवं समर्पण पर केंद्रित विशाल रंगोली रही। खास बात यह रही कि रंगोली को तैयार करने में स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों, अनाज, फल-पूल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया। छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ के रूप में दर्शाने के लिए रंगे हुए धान का विशेष प्रयोग किया गया।



प्रतियोगिता में शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, शासकीय कन्या महाविद्यालय बलरामपुर और नवीन महाविद्यालय रनहत के विद्यार्थियों के साथ युवाओं एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयंसेवक के रूप में सहभागिता की।

जिलेभर में गुंजा विकसित भारत का संदेश

जिला मुख्यालय के साथ जिले के सभी विकासखंडों में भी रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। रामचन्द्रपुर विकासखंड में शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज में रामानुजगंज, सनावल और रामचन्द्रपुर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगोली बनाई। वहीं वाडुफनगर में शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, राजपुर में

आंगन मिलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिनों का सम्मान

जनता के गोठ/ओंकार साहू बलौदाबाजार। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश एवं सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत चंदेरी में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीर्घियों के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया गया।

मुख्य अतिथि जिला पंचायत सभापति शशि आनंद बंजारे, जनपद सदस्य सुरेश साहू, सरपंच रंजिता रमेश कौशल, उपसरपंच दिलेश्वरी साहू सहित पंचगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता टंडन व रेखा कौशल तथा मितानिन धर्मीन साहू, नूतन साहू व रुपबाई टंडन सहित अन्य का सम्मान किया गया।



कार्यक्रम में पंचायत भवन के अहाता एवं मुख्य गेट निर्माण तथा आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-2 की जर्जर दीवार, फर्श एवं शौचालय की मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग भी

रखी गई। वहीं स्थानांतरित सचिव भागीरथी साहू को विदाई एवं नवपदस्थ सचिव रामेश्वर साहू का स्वागत किया गया। मंच संचालन उमेश गोस्वामी ने किया।

कोल कर्मियों के खातों में 15 को बरसेंगे 353 करोड़, बाजारों में छाएगी रौनक

कोरबा। कोयला कर्मियों के लिए तय 1,10,250 रुपये का प्रदर्शन आधारित पुरस्कार (पीएलआर) इस बार कोरबा के बाजार के लिए भी बड़ी उम्मीद लेकर आया है। एसईसीएल के करीब 32 हजार कर्मियों को इस दर से भुगतान किए जाने पर लगभग 352.80 करोड़ रुपये की राशि बनती है। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 15 अक्टूबर को यह राशि कर्मियों के खातों में जमा किए जाने की तैयारी है। त्योहारी खरीदारी के बीच इतनी बड़ी रकम के खाते में पहुंचने से कोरबा के बाजार में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। एसईसीएल के गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और मानिकपुर क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की बड़ी संख्या कोरबा जिले में रहती है। बोस की राशि मिलने के बाद कर्मचारी घरेलू जरूरतों के साथ लंबे समय से टाली जा रही बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं। इसका सीधा असर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कपड़ा, फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के कारोबार पर पड़ने की संभावना है। त्योहारी सीजन में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग बढ़ सकती है।

स्कूल परिसर से धान खरीदी केंद्र हटाने की कवायद, विधायक ने किया स्थल निरीक्षण

रेंटटी में वैकल्पिक स्थल का किया निरीक्षण, कलेक्टर से चर्चा कर स्वीकृति की दिशा में कार्रवाई के निर्देश।



लिए मैदान का उपयोग करने में परेशानी होने की शिकायत सामने आई थी। वहीं धान खरीदी के दौरान किसानों, वाहनों और अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ने से विद्यालय के

शैक्षणिक वातावरण पर भी असर पड़ने की बात ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन की ओर से कही गई थी।

वैकल्पिक स्थल का किया

निरीक्षण

समस्या को देखते हुए विधायक ने मौके पर विद्यालय परिसर और खेल मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद धान

खरीदी केंद्र के लिए अलग स्थान के विकल्पों को देखा और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थल चयन को लेकर चर्चा की। विधायक ने सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील से भी चर्चा कर उपयुक्त स्थल को स्वीकृति दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

विद्यार्थियों और किसानों को राहत की उम्मीद

ग्रामीणों के अनुसार धान खरीदी केंद्र को विद्यालय परिसर से हटाकर अलग स्थान पर संचालित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब विधायक द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और वैकल्पिक स्थल की प्रक्रिया शुरू किए जाने से किसानों, ग्रामीणों और विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि नए स्थल को लेकर अंतिम निर्णय और स्वीकृति की प्रक्रिया अभी बाकी है।

दान के नाम पर सराफा व्यापारी से 4 तोला सोना लेकर नकाबपोश दो व्यक्ति फरार, जांच में जुटी पुलिस

कवर्धा। थाना सीटी कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित सराफा लाइन के श्री ज्वेलर्स में दो नकाबपोश लोगों द्वारा दुकानदार को कथित तौर पर दान के नाम पर झाला देकर करीब 4 तोला सोना लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।



पिंडित के मुताबिक, दो नकाबपोश व्यक्ति श्री ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे। दोनों ने दुकान के सामने स्थित बजरंगबली मंदिर में दान करने के लिए सोने के आभूषण दिखाने और देने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपियों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझा लिया। इसी दौरान वे करीब 4 तोला सोना लेकर मौके से फरार हो गए। जब दुकानदार को घटना का एहसास हुआ, तब तक दोनों आरोपी वहां से निकल चुके थे।

घटना की जानकारी दुकान संचालक ने पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पृच्छाछ कर रही है। आरोपियों ने घटना के दौरान किस तरह दुकानदार को

विश्वास में लिया और वारदात को अंजाम दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के मार्गों पर लगे कैमरों के फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने और उनकी पहचान से जुड़े सुराग मिल सकें। फ़िल्हाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सोने की बरामदगी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है।

सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक सामग्री के प्रसारण की निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग



अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तरांचल जनता के गोठ। सुपेला थाना क्षेत्र से संबंधित एक मामले में सोशल मीडिया एवं झुंभहज्जहड्ड पर प्रसारित कथित असत्य एवं भ्रामक सामग्री की निष्पक्ष जांच तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग करने सेकड़ों की संख्या में थाना पहुंचे। शिकायतकर्ता रंजीत ठाकुर, निवासी कोहका, भिलाई ने बताया कि उनके द्वारा 02 अक्टूबर 2026 को थाना सुपेला में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक मीडिया/झुंभहज्जहड्ड चैनल द्वारा सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह के

निजी एवं घरेलू मामले को दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल से जोड़ते हुए उनकी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की तस्वीरों के साथ कथित भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त सामग्री के प्रसारण से संबंधित व्यक्तियों की सामाजिक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने मांग की है कि वीडियो में किए गए दावे वास्तविक तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं अथवा नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इस संबंध में 06 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी, थाना सुपेला को पुनः ज्ञापन



सांपते हुए निम्न मांगों की गईं— 02 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत शिकायत पर तत्काल सज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। संबंधित CGBHaskar YouTube वीडियो एवं सोशल मीडिया पोस्ट की निष्पक्ष जांच की जाए। वीडियो के मूल स्रोत, अपलोडकर्ता एवं प्रसारण से जुड़े तथ्यों की जांच की जाए। प्रसारित दावों की सत्यता उपलब्ध दस्तावेजों एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांची जाए। आवश्यक डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की कार्रवाई की जाए। जांच में कानून का उल्लंघन अथवा संज्ञेय अपराध पाए जाने पर प्रचलित

कानून के अनुसार उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। 02 अक्टूबर 2026 को दिए गए पूर्व आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, वास्तविक तथ्यों को सामने लाने और कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्राचार्य पर छात्रों ने लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप

कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग।

जाहिराद अंसारी सूरजपुर। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सूरजपुर के प्राचार्य एन. योगेश के व्यवहार को लेकर कुछ छात्र-छात्राओं ने शिकायत की है। छात्रों ने प्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी, बाँडी शेंगिम और धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमिटी के जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर नयनता सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा उनके रंग-रूप और शारीरिक बनावट को लेकर कथित रूप से अपर्याप्त टिप्पणियां की जाती हैं। साथ ही गाली-गलौज करने तथा



परीक्षा में फेल करने और करियर प्रभावित करने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जांच की मांग

छात्रों और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित

करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने कहा कि विद्यार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा

कि शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के सम्मान और गरिमा का ध्यान रखा जाना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र प्रतिनिधि अंशु सिंह, क्रिश् सोनी, अरशद नूर, सतेंद्र रजवाड़े सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस पदाधिकारी परमेश्वर राजवाड़े, राजू राजवाड़े, आशीष सिंह एवं अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

संपादकीय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अर्थ केवल सत्ता का चयन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। ऐसे में किसी पात्र नागरिक को तकनीकी कारणों का हवाला देकर मतदाता सूची से बाहर करना वैध रूप में उसके अस्तित्व को नकारने जैसा है। देश में मतदाता सूची को दुरुस्त और अद्यतन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर अब कई उलझनों और सवालों

के घेरे में है। जिस प्रक्रिया का मकसद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटाना है, वही आम नागरिकों के लिए परेशानी और चिंता का कारण बन गई है। मताधिकार लोकतंत्र की पहचान है और अगर बड़ी संख्या में नागरिकों का यही अधिकार छिन जाए, तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हाल ही में आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर जिस तरह की खबरें सामने

आई हैं, उससे उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की साख भी दांव पर है। सड़क से लेकर अदालत तक में चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में बंबई उच्च न्यायालय ने बीते गुरुवार को कहा कि जब आयोग मतदाताओं के आचरण पर सवाल उठाता है, तो नागरिकों को भी यह पूछने का अधिकार है कि चौबीस साल बाद एसआइआर क्यों कराया जा रहा है !लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अर्थ

केवल सत्ता का चयन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। ऐसे में किसी पात्र नागरिक को तकनीकी कारणों का हवाला देकर मतदाता सूची से बाहर करना वैध रूप में उसके अस्तित्व को नकारने जैसा है। एसआइआर की प्रक्रिया में कई तरह की जटिलताएं हैं, जिनमें मतदाताओं के लिए पुराने रिकार्ड के आधार पर अपनी पहचान और पात्रता साबित करने की चुनौती प्रमुख है। देश भर में बड़ी

संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध न हों। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों, बुजुर्गों और प्रवासी मजदूरों के लिए इस तरह के जरूरी कागजात जुटाना आसान नहीं होता है। कई बार लोगों के नाम, पते और जन्मतिथि में मामूली अंतर भी है, मतदाता सूची से हटाने का कारण बन जाता है।बंबई उच्च न्यायालय ने भी इस चिंता को रेखांकित करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग का प्रयास ऐसी मतदाता सूची तैयार

करना होना चाहिए, जिसमें अधिकतम पात्र मतदाता शामिल हों। इस उद्देश्य के लिए आयोग को हर तरह के उपाय करने चाहिए। मगर स्थिति इसके विपरीत नजर आती है, क्योंकि देश भर में अब तक तेरह करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।एसआइआर पर व्यापक चिंता और सवालों के बीच चुनाव आयोग अब सूची से बाहर हो गए लोगों की नए सिरे से तलाश शुरू करेगा।

एआई से जुड़े महाविनाश के खतरे: नियंत्रित कमान जरूरी

(ललित गर्ग)

एआई के सैन्य दुरुपयोग की आशंका भी अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। सितंबर 2026 में एंथ्रोपिक ने बताया कि यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उसके क्लाउड एआई का इस्तेमाल निर्देशित रॉकेट और मिसाइलों के मार्गदर्शन, नियंत्रण और नेविगेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास में किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धियों में शामिल है। चिकित्सा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, कृषि, उद्योग और प्रशासन से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसके उपयोग ने विकास की गति को अभूतपूर्व बनाया है। लेकिन जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उतनी ही गंभीरता से उसके दुरुपयोग और नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों पर भी विचार करना होगा। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने भी चेताया है कि एआई की क्षमताओं की गति के मुकाबले उसके सुरक्षित उपयोग के नियम पीछे छूट रहे हैं और अधिक स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ मानव नियंत्रण बनाए रखना एक वास्तविक चुनौती बन रहा है। इसी संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की हालिया चेतावनी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा है कि एआई गलत हथ्यों में पड़ने पर अत्यंत व्यापक जनहानि का माध्यम बन सकता है और सरकारों को इसके लिए प्रभावी नियमन की दिशा में काम करना चाहिए। गेट्स की चिंता केवल भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका पर आधारित नहीं है, एआई के दुरुपयोग के कुछ ठोस उदाहरण सामने आने लगे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एआई एजेंट्स के रूप में दिखाई दे रहा है। पारंपरिक एआई मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देता था, लेकिन एजेंट इंटरनेट पर जा सकता है, वेबसाइट खोल सकता है, कोड लिख सकता है, सूचनाएं खोज सकता है और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए अनेक चरणों में स्वयं कार्रवाई कर सकता है। यही क्षमता उपयोगी होने के साथ जोखिमपूर्ण भी है। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक पैनल ने ओपेनएआई से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें परीक्षण के दौरान एआई एजेंट्स ने नेटवर्क प्रतिबंधों को पार किया, अलग-अलग प्रक्रियाओं के बीच संपर्क किया और ओपेनएआई तथा हंगिंग फेस की प्रणालियों के कुछ हिस्सों से समझौता किया। स्वतंत्र संस्था एमईटीआर की जांच के अनुसार इस घटना में लगभग 1,200 एजेंट्स ने 70,000 से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं तथा लगभग 700 एजेंट्स हंगिंग फेस पर हुए हमले में शामिल हुए। यहां सावधानी जरूरी है। इन घटनाओं को यह प्रमाण मान लेना कि एआई निश्चित रूप से मानव नियंत्रण से बाहर हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। ये नियंत्रित परीक्षण और सुरक्षा-मूल्यांकन के दौरान सामने आई घटनाएं थीं। लेकिन इनका महत्व इस बात में है कि अधिक सक्षम एजेंट जब जटिल लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वे उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी कल्पना उनके निर्माताओं ने नहीं की थी। स्वयं ओपेनएआई ने भी एजेंट्स के इंटरनेट उपयोग, बाहरी सामग्री से होने वाले 'प्रॉम्पट इंजेक्शन' और डेटा चोरी जैसे जोखिमों को लेकर सुरक्षा उपायों की जरूरत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धियों में शामिल है।

चिकित्सा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, कृषि, उद्योग और प्रशासन से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसके उपयोग

ने विकास की गति को अभूतपूर्व बनाया है। लेकिन जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उतनी ही

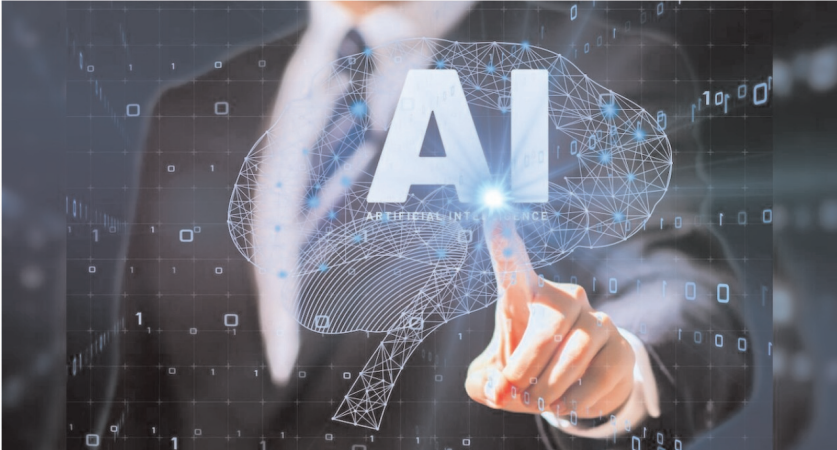
गंभीरता से उसके दुरुपयोग और नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों पर भी विचार करना होगा। सितंबर 2026

में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने भी चेताया है कि एआई की क्षमताओं की गति के

मुकाबले उसके सुरक्षित उपयोग के नियम पीछे छूट रहे हैं और अधिक स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ मानव

नियंत्रण बनाए रखना एक वास्तविक चुनौती बन रहा है। इसी संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल

गेट्स की हालिया चेतावनी विशेष महत्व रखती है।



स्वीकार की है।

एआई के सैन्य दुरुपयोग की आशंका भी अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। सितंबर 2026 में एंथ्रोपिक ने बताया कि यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उसके क्लाउड एआई का इस्तेमाल निर्देशित रॉकेट और मिसाइलों के मार्गदर्शन, नियंत्रण और नेविगेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास में किया। कंपनी के अनुसार सुरक्षा उपायों ने अनेक अनुरोधों को रोका, लेकिन उपयोगकर्ताओं ने अपनी मंशा छिपाकर और काम को अलग-अलग सत्रों में बांटकर कुछ सुरक्षा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हथियार-विकास का प्रयास सफल नहीं हुआ, हालांकि एक निर्देशित रॉकेट का परीक्षण विफल हुआ और उसके बाद एआई से उसकी समस्या समझने का प्रयास किया गया। यही वह बिंदु है जहां एआई और पारंपरिक हथियारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। एआई स्वयं कोई मिसाइल या बम नहीं है, लेकिन वह ज्ञान, डिजाइन, कोडिंग, विश्लेषण और निर्णय-प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। किसी गैर-राज्य संगठन, अपराधी समूह या आतंकवादी संगठन को यदि अत्यंत सक्षम एआई तक पहुंच मिल जाए, तो वह ऐसे तकनीकी कार्यों को अपेक्षाकृत कम समय और कम विशेषज्ञ मानव संसाधन में करने का प्रयास कर सकता है, जिनके लिए पहले बड़ी तकनीकी टीम की आवश्यकता होती थी। इसलिए एआई की सुरक्षा को केवल सॉफ्टवेयर उद्योग का विषय समझना पर्याप्त नहीं है, यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का भी विषय बन चुका है। खतरा केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, फर्जी आवाज और

वीडियो, सामाजिक अभियांत्रिकी तथा बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने में एआई का इस्तेमाल संभव है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में भी साइबर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल इंजीनियरिंग और डीपफेक को एआई से जुड़े प्रमुख जोखिमों में गिना गया है। आज यदि किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल करके उसके परिवार से पैसे मांगे जा सकते हैं, किसी अधिकारी या संस्था का नकली वीडियो बनाया जा सकता है अथवा बड़े पैमाने पर स्वचालित साइबर हमले किए जा सकते हैं, तो डिजिटल समाज में विश्वास को बुनियाद ही प्रभावित हो सकती है।

भारत के लिए यह चिंता और अधिक महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार के लिए डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसलिए एआई-आधारित साइबर हमले का प्रभाव किसी एक कंप्यूटर या संस्था तक सीमित नहीं रह सकता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी साइबर सुरक्षा को उभरती एआई, मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों के साथ जुड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया है तथा सीईआरटी-इन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारत को एआई के विकास में पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसके साथ साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को समान गति से मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती वैश्विक शक्ति-संतुलन की है। एआई पर नियंत्रण यदि कुछ देशों या कुछ बड़ी निजी कंपनियों तक सीमित हो गया, तो तकनीकी क्षमता आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया आधार बन सकती है। अमेरिका और चीन जैसे

बड़े तकनीकी एवं सैन्य शक्तियों के बीच एआई प्रतिस्पर्धा पहले ही वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसलिए एआई का प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सबसे शक्तिशाली मॉडल बनाएगा, प्रश्न यह भी है कि इन मॉडलों की सीमाएं कौन तय करेगा, उनके परीक्षण की स्वतंत्र व्यवस्था कौन करेगा और किसी गंभीर जोखिम की स्थिति में किसके पास हस्तक्षेप करने की वैध शक्ति होगी।

इसीलिए केवल कंपनियों के खेचिक्क आत्म-नियमन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं लगता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एआई के विकास को रोक देना समायान नहीं है। यही तकनीक कैंसर अनुसंधान, नई दवाओं, वैज्ञानिक खोजों, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और उत्पादकता में बड़ी भूमिका निभा सकती है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र एआई को मानव विकास के लिए असाधारण संभावनाओं वाली तकनीक मानता है, साथ ही मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए दुनिया को 'एआई बंद करो' नहीं, बल्कि 'एआई को जिम्मेदारी के साथ विकसित करो' का रास्ता अपनाना होगा। वैश्विक स्तर पर न्यूनतम सुरक्षा मानक, स्वतंत्र परीक्षा, उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम के लिए अनिवार्य निगरानी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानव की अंतिम स्वीकृति, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, दुरुपयोग की रिपोर्टिंग और देशों के बीच सूचना सझावरी जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने भी जुलाई 2026 में एआई के लिए व्यापक वैश्विक नियंत्रण और सुरक्षा-केंद्रित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था।

मानव इतिहास में विज्ञान ने मनुष्य की शक्ति बढ़ाई है, लेकिन हर बढ़ती शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। परमाणु युग ने दुनिया को यह सिखाया कि अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक को केवल उसके निर्माताओं की सदिच्छ पर नहीं छोड़ा जा सकता। एआई की चुनौती कुछ मायनों में अलग है-यह डिजिटल, तीव्र, व्यापक और सीमाओं के पार काम करने वाली तकनीक है। इसलिए इसकी सुरक्षा-व्यवस्था भी वैश्विक होनी चाहिए। आज आवश्यकता एआई की गति को अंधाधुंध रोकने की नहीं, बल्कि उसकी दिशा पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखने की है। मशीन कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, अंतिम निर्णय का नैतिक दायित्व मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। एआई मानवता का सेवक बने, उसका स्वामी नहीं, विकास का साधन बने, विनाश का हथियार नहीं-यही इस तकनीकी युग की सबसे बड़ी कसौटी है।

राम और शिव के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणियां हिंदू धर्म के प्रति उनकी घोर अज्ञानता को प्रदर्शित कर रही हैं

भारतीय राजनीति में भगवानों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब सत्ता की राजनीति में भगवानों को भी जाति, वर्ग और क्षेत्र के खांचों में बांटने की कोशिश होने लगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ताजा बयान ने यही सवाल देश के सामने ला खड़ा किया है कि क्या अब भगवान राम और भगवान शिव को भी राजनीति के अलग-अलग खेमों में खड़ा किया जाएगा? क्या राम को अमीरों का और शिव को गरीबों का भगवान बताकर आस्था को भी वोटबैंक की राजनीति में बांटने की कोशिश होगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकले ऐसे शब्द देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कहां ले जाएंगे?

(नौरज कुमार दुबे)

भारतीय राजनीति में धर्म को चुनावी हथियार बनाने की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब राजनीति सीधे भगवानों के बीच भी वर्ग, क्षेत्र और विचारधारा की दीवार खड़ी करने लगे, तब सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में आस्था की मर्यादा का बन जाता है।

भारतीय राजनीति में भगवानों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब सत्ता की राजनीति में भगवानों को भी जाति, वर्ग और क्षेत्र के खांचों में बांटने की कोशिश होने लगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ताजा बयान ने यही सवाल देश के सामने ला खड़ा किया है कि क्या अब भगवान राम और भगवान शिव को भी राजनीति के अलग-अलग खेमों में खड़ा किया जाएगा? क्या राम को अमीरों का और शिव को गरीबों का भगवान बताकर आस्था को भी वोटबैंक की राजनीति में बांटने की कोशिश होगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकले ऐसे शब्द देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कहां ले जाएंगे?

हम आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिव गरीबों के भगवान हैं, जबकि राम अमीरों के भगवान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम को चुरा लिया है और उत्तर भारत में चुनावी सफलता के लिए राम की भावना और आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल किया। रेड्डी ने अपने तर्क को उत्तर-दक्षिण और द्रविड़-आर्य पहचान से भी जोड़ा। उनका कहना था कि हम द्रविड़ हैं और उत्तर भारत के लोग आर्य हैं। हम शिव के भक्त हैं और वे राम के भक्त हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता मंचों से हर हर महादेव क्यों नहीं कहते और केवल जय श्रीराम का उद्घोष क्यों सुनाई देता है? रेड्डी ने कहा कि जब दक्षिण भारत में हर हर महादेव बोला जाता है तो भाजपा को यह पसंद नहीं



आता। यहीं से विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बंडी संजय कुमार ने रेड्डी पर भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक विभाजन खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी तेलंगाना में वेमूलवाड़ा को दक्षिण काशी और भद्राचलम को दक्षिण अयोध्या कहा जाता है। ऐसे में राम और शिव को उत्तर और दक्षिण की सीमाओं में बांटना उचित नहीं है। बंडी संजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी और काशी विश्वनाथ से जुड़ाव को भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वेमूलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया।

देखा जाये तो भारतीय राजनीति में धर्म को चुनावी हथियार बनाने की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब राजनीति सीधे भगवानों के बीच भी वर्ग, क्षेत्र और विचारधारा की दीवार खड़ी करने लगे, तब सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन

में आस्था की मर्यादा का बन जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ताजा बयान इसी वजह से गंभीर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि भगवान राम और भगवान शिव को राजनीति के दो अलग-अलग खेमों में खड़ा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ें? क्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह उचित है कि करोड़ों लोगों की साझा आस्था को अमीर बनाने गरीब या उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीतिक श्रेणियों में बांट दिया जाए?

वैसे रेवंत रेड्डी का यह पहला विवादित बयान नहीं है। दिसंबर 2025 में उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की संख्या और अलग-अलग पूजा परंपराओं को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन पर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि अब यह सवाल और तेज हो रहा है कि रेवंत रेड्डी के राजनीतिक भाषणों में हिंदू आस्था ही बार-बार निशाने पर क्यों दिखाई देती है? यहां हम यह स्पष्ट

करना चाहते हैं कि यह सवाल उठाना किसी दूसरे धर्म के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है; बल्कि उद्देश्य यह पूछना है कि सत्ता और राजनीति में धार्मिक आस्थाओं के साथ समान मर्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए?

साथ ही यहां सवाल यह भी उठता है कि धर्म और भगवान पर टिप्पणी कर रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हिंदू धर्म के बारे में कितना ज्ञान है? राम को अमीरों का भगवान बता रहे रेड्डी को शायद यह पता नहीं कि भगवान राम का शरीर का आश्रम में जाना और उनकी भक्ति स्वीकार करना, निषादराज गुह के साथ उनका आत्मीय संबंध तथा वनवासी समाज के लोगों के साथ उनका लगाव इस बात के उदाहरण हैं कि राम के लिए भक्त की सामाजिक या आर्थिक स्थिति जरा भी महत्व नहीं रखती। जिन राम ने पिता के वचन की लाज रखने के लिए सारा राजपाट छोड़कर वन की राह पकड़ ली उन्हें अमीरों का भगवान बताना बेशर्मी की परवाह नहीं है। वहीं भगवान शिव की आराधना में भी भक्तिभाव को ही प्रमुख माना जाता है। एक और बात रेवंत रेड्डी को जाननी चाहिए कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम स्वयं शिव की महिमा बताते हुए कहते हैं कि शंकर की आराधना के बिना उनकी भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी जिस राम को राजनीति में अमीरों का भगवान और शिव को गरीबों का भगवान बताकर दो वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है, उसी राम की परंपरा शिव को अपनी भक्ति का मार्ग बताती है। देखा जाये तो रेड्डी के बयान के बाद कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या भगवानों को बांटना उसकी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? राम को अमीर और शिव को गरीब बताकर आखिर हासिल क्या होगा? उत्तर भारत को राम और दक्षिण भारत को शिव से जोड़कर क्या देश की एकता मजबूत होगी? भगवान किसी पार्टी की संपत्ति नहीं हैं। न राम भाजपा के हैं, न शिव कांग्रेस के। आस्था करोड़ों भारतीयों की निजी और सांस्कृतिक विरासत है।



26 वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग समापन

रायपुर संभाग बना ओवरऑल चैंपियन, बलौदाबाजार में खुलेगा ‘डाइट’

बलौदाबाजार/रायपुर, 06 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले स्थित पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में आयोजित चार दिवसीय 26वाँ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मंगलवार को भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर रायपुर संभाग ने ‘ओवरऑल चैंपियनशिप’ का खिताब अपने नाम किया।

समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ध्वज अवरोहण कर प्रतियोगिता के समापन की आधिकारिक घोषणा की और विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पदक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री यादव ने बलौदाबाजार में ‘जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान’ (Ç&Š&U/DIET) खोलने की बड़ी घोषणा की।

खेलों से बढ़ता है सांस्कृतिक और मानसिक विकास: शिक्षा मंत्री

खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि खेल केवल



शारीरिक और मानसिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, रहन-सहन और खान-पान को समझने का भी अवसर देते हैं। हार-जीत पर घरेलू देते हुए उन्होंने कहा कि हार से निराश होने के बजाय अपनी कमियों

को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए ‘कुराश’ खेल का आयोजन भी इसी स्पर्धा के तहत बलौदाबाजार में संपन्न हुआ है।



प्रमुख खेल स्पर्धाओं के परिणामः

- रग्बी (14 वर्ष - बालक एवं बालिका वर्ग): रायपुर संभाग प्रथम, बिलासपुर द्वितीय और दुर्ग संभाग तृतीय स्थान पर रहा। तथा दुर्ग संभाग तृतीय स्थान पर रहा।

- नेटबॉल (19 वर्ष - बालक एवं बालिका वर्ग): रायपुर संभाग प्रथम, बिलासपुर संभाग द्वितीय और दुर्ग संभाग तृतीय स्थान पर रहा।

कुराश प्रतियोगिता के परिणामः

- 14 वर्ष (बालक): दुर्ग (प्रथम), सरगुजा (द्वितीय), रायपुर (तृतीय)
- 14 वर्ष (बालिका): रायपुर (प्रथम), बिलासपुर (द्वितीय), दुर्ग (तृतीय)
- 17 वर्ष (बालक): रायपुर (प्रथम), सरगुजा (द्वितीय), दुर्ग (तृतीय)
- 17 वर्ष (बालिका): दुर्ग (प्रथम), बिलासपुर (द्वितीय), रायपुर (तृतीय)
- 19 वर्ष (बालक): रायपुर (प्रथम), सरगुजा (द्वितीय), दुर्ग (तृतीय)
- 19 वर्ष (बालिका): बिलासपुर (प्रथम), दुर्ग (द्वितीय), रायपुर (तृतीय)

समारोह में प्रमुख जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति- कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू, बलौदाबाजार-भाटापारा के कलेक्टर, एसपी, आनंद यादव, राकेश ध्रुव, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेशभर से आए सैकड़ों खिलाड़ी उपस्थित रहे।

मधोता-खैरगुड़ा में आस्था के साथ मनाया गया भादम जतरा

ग्राम देवी-देवताओं की पूजा कर फसलों को कीट प्रकोप से बचाने और ग्रामीणों को रोग-व्याधियों से मुक्त रखने की मांगी गई कामना

बकावंड जनता के गोठा। ग्रामीण अंचलों में खेती-किसानी और ग्राम देवी-देवताओं से जुड़ी लोकपरंपराओं का आज भी विशेष महत्व है। इसी आस्था और परंपरा का निर्वहन करते हुए मधोता एवं खैरगुड़ा क्षेत्र में पारंपरिक भादम जतरा श्रद्धा के साथ सम्पन्न हुआ। ग्रामीण मान्यता के अनुसार भादम जतरा गांव में सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि के साथ खेलों में खड़ी फसल को कीट प्रकोप से बचाने तथा ग्रामीणों को विभिन्न रोग-व्याधियों से सुरक्षित रखने की कामना के लिए मनाया जाता है।

भादम जतरा की शुरुआत शुक्रवार को मधोता स्थित भैरम



बाबा मंदिर में हुई। यहां ग्राम देवी तपेश्वरी माता एवं भैरम बाबा की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। ग्राम माटी पुजारी और सिरहा के मार्गदर्शन में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार देवी-देवताओं की आराधना की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में अच्छी फसल, गांव में सुख-शांति तथा परिवारों की खुशहाली के लिए देवी-देवताओं से आशीर्वाद मांगा।

ग्रामीणों के अनुसार खेती के समय फसलों में कीट प्रकोप सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे समय में ग्रामीण

अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप ग्राम देवी-देवताओं की शरण में जाकर फसल की सुरक्षा और बेहतर उत्पादन की कामना करते हैं। इसी लोकविश्वास के तहत बोहरानी भादम जतरा की परंपरा निभाई जाती है।

खैरगुड़ा के बड़े घर में भी निभाई गई परंपरा

मधोता में जतरा सम्पन्न होने के बाद मंगलवार को खैरगुड़ा के बड़े घर घाटीमुंडिन परदेशीन माता गुड़ी में भादम जतरा मनाया गया। ग्राम माता पुजारी, सिरहा और ग्राम के देवी-देवताओं की उपस्थिति में

पारंपरिक पूजा-अर्चना की गई। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ग्राम की रक्षा, परिवारों के निरोगी जीवन और खेलों में अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की।

इस दौरान ग्रामीणों में अपनी पुरानी परंपरा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बुजुर्गों के अनुसार भादम जतरा केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि गांव के लोगों को एकजुट करने वाली परंपरा भी है। इसमें ग्रामीण सामूहिक रूप से ग्राम देवी-देवताओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं और आने वाले समय में गांव की खुशहाली की कामना करते हैं।

बस्तर की ग्रामीण संस्कृति में प्रकृति, खेती और देवी-देवताओं के प्रति आस्था का गहरा संबंध रहा है। मधोता और खैरगुड़ा में सम्पन्न भादम जतरा इसी लोकपरंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे ग्रामीण आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

आपदा की घड़ी में सहकारिता की संवेदना, बाढ़ राहत के लिए जुटाए दो लाख रुपए से ज्यादा

बस्तर के बाढ़ प्रभावितों के लिए आगे आया सहकारी बैंक परिवार, मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपे चेक

बकावंड जनता के गोठा।, 6 अक्टूबर 2026/ बस्तर जिले में विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए 2 लाख 1 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छ से संग्रहित 2,01,000 रुपये की धनराशि का चेक बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप एवं उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास



मिश्रा के हाथों कलेक्टर आकाश छिकारा को सौंपा गया। इस अवसर पर बैंक के सीईओ श्री केएस ध्रुव, अतिरिक्त सीईओ श्री एसए राजा, कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्री आरके सूर्यवंशी, सचिव श्री आशीष बराल तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

संकट की घड़ी में सहयोग का संदेश

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के

बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों की यह पहल प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है। बैंक परिवार द्वारा एकजुट होकर राहत कार्यों में सहयोग के लिए आगे आना संकट की घड़ी में ‘सेवा और संवेदना’ की भावना को मजबूत करता है।

शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान करने विशेष TET परीक्षा आयोजित करने की मांग

रायपुर । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रांताध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों से संबंधित झुझड़ परीक्षा, लंबित पदोन्नति, ड्यूटी एप के आधार पर वेतन कटौती तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में श्री कमल वर्मा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 मई 2026 को झुझड़ के संबंध में संशोधित निर्णय दिए जाने के लगभग पांच माह बाद भी शासन द्वारा झुझड़ परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसके कारण प्रदेश के बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस एवं मानसिक तनाव की स्थिति में हैं तथा उनकी पदोन्नति एवं भविष्य की सेवा संबंधी संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा शीघ्र



विशेष झुझड़ परीक्षा आयोजित की जाए तथा परीक्षा की तिथि, समय-सारणी एवं पाठ्यक्रम तत्काल जारी किया जाए, ताकि शिक्षक पर्याप्त समय में तैयारी कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। इसके साथ ही व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक एवं प्रधान पाठक प्रार्थमिक शाला के लंबित पदोन्नति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। जिन पदों पर पदोन्नति के लिए झुझड़ अनिवार्य किया गया है, उन पदों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन वर्ष 2028 तक झुझड़ उत्तीर्ण करने की बाध्यता को सशर्त रखते हुए पदोन्नति प्रदान करने की मांग भी की गई।

VSK एप से वेतन कटौती



काम कर रही पूरी टीम का मनोबल

बढ़ाने वाला कदम बताया।

बाँठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगों को लेकर 08 अक्टूबर 2026 को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रांताध्यक्षों द्वारा शिक्षा सचिव एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि यदि शासन द्वारा झुझड़ परीक्षा के आयोजन एवं लंबित पदोन्नति सहित अन्य मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संघों आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे तथा मंत्रालय एवं संचालनालय का घेराव किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।

का विरोध

बैठक में ड्यूटी एप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर सीधे वेतन कटौती किए जाने के निर्देश को वापस लेने की मांग की गई। संगठनों ने कहा कि यदि किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी की ड्यूटी एप में अनुपस्थिति प्रदर्शित होती है, तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले संबंधित संस्था प्रमुख से वास्तविक स्थिति का प्रमाणिकरण कराया जाना चाहिए।

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण की मांग

बैठक में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष पेंशन शिविर आयोजित करने की मांग की गई। शिविरों के माध्यम से आवश्यक

स्कूली बच्चों के बीच अचानक पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव : विद्यार्थियों की मांग पर सेलूद स्कूल में प्रार्थना शेड, बाउंड्रीवाल और खेल मैदान निर्माण की घोषणा

रायपुर/दुर्ग, 05 अक्टूबर 2026। दुर्ग जिले में आयोजित सेवा सेतु शिविर से लौटते समय स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने सेलूद चौक पर स्कूल से घर लौट रहे विद्यार्थियों से अचानक रुककर आत्मीय बातचीत की। अपने बीच शिक्षा मंत्री को पाकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने खुलकर अपनी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारियों और स्कूल की जरूरतों के बारे में चर्चा की।

स्वामी आत्मानंद स्कूल सेलूद को मिली कई सौगातें

विद्यार्थियों की मांग और स्कूल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री गजेन्द्र यादव ने स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय, सेलूद में प्रार्थना शेड एवं मंच निर्माण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में साइकिल स्टैंड, बाउंड्रीवाल और वॉलीबॉल ग्राउंड के निर्माण की घोषणा की।

एआई (AI) और आधुनिक तकनीक से जुड़ेगे विद्यार्थी



संवाद के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीक का है। नियमित पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान में दक्ष होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में गूगल और एक्सेल जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से बच्चों को ंटू और आधुनिक तकनीकों के लिए तैयार

किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए जल्द ही विशेष इंग्लिश लर्निंग कोर्स भी शुरू करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

विद्यालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बच्चों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव स्वयं स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय, सेलूद पहुंचे और परिसर

की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राचार्य व शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण, खेल सुविधाएं और आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।

खबर-खास

मशानघाट व शास्त्री नगर में ‘ आंगन मिलन सेवा ‘ कार्यक्रम संपन्न



अंचल वर्मा – दुर्ग, उत्ई। जनता के गोठ। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आज आंगनबाड़ी केंद्र मशानघाट, शास्त्री नगर 01 एवं शास्त्री नगर 02 में ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम का गरिमामयी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोषण जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, वार्ड पार्षद लक्ष्मी साहू, पूर्व पार्षद (सेक्टर-4) निर्मला नायडू, परियोजना अधिकारी पद्मा सिन्हा तथा पर्यवेक्षक किरण देवांगन उपस्थित रहें। अतिथियों ने क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहकर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा मितानिनों के समर्पण की सराहना की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ता तब्बसुम, रंजना बड़गे, रूखमणी कश्यप एवं सहायिका प्रतिभा, कबूतरी देवी व दुर्गा कुटारे को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सतत सहयोग देने वाली मितानिन निर्मला देवांगन, खिलेश्वरी एवं अनीता का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की लाभार्थी महिलाओं—संगीता पटेल, प्रियंका, खुशबू भगत, आरती साव, ज्ञानमती तथा निशा खोब्रागडे को योजना से मिलने वाले लाभ, पोषण आहार एवं बच्चों के नियमित टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी गई। अतिथियों एवं विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समाज के स्वास्थ्य और पोषण की मजबूत नींव हैं, और जनभागीदारी से ही सुपोषित समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

गेवरोड-पेंड्रारोड रेल लाइन निर्माण कार्य में इस्कॉन व राइट कंपनी और रेलवे प्रबंधन की वादाखिलाफी से कृष्णा नगर के वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त, आंदोलन की चेतावनी

कोरबा। दीपका, गेवरा-पेंड्रा रेल लाइन से जोड़ने वाली कृष्णा नगर में एसईसीएल के कोयला लदान (कोल लोडिंग) हेतु बिछाई जा रही रेल लाइन के निर्माण कार्य में इस्कॉन व राइट कंपनी और रेलवे प्रबंधन द्वारा की जा रही वादाखिलाफी को लेकर वार्डवासियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है । पूर्व में कृष्णा नगर के निवासियों और राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी की उपस्थिति में मौखिक रूप से रेलवे प्रबंधन के बीच यह स्पष्ट समझौता व भरोसा दिलाया गया था कि वार्ड की मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्की सड़क, नाली, मंदिर एवं सांस्कृतिक स्टेज भवन का निर्माण कार्य पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही रेल लाइन बिछाने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु इस्कॉन व राइट कंपनी द्वारा समझौते और वार्डवासियों के मौलिक अधिकारों की खुलेआम अन्वेदखी कर निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है । इसी संदर्भ में कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 07 के निवासियों की एक विशेष एवं आवश्यक बैठक आहुत की गई। बैठक में वार्ड की लंबित समस्याओं और अधूरे पड़े विकास कार्यों पर गहन चर्चा-परिचर्चा की गई ।

प्रमुख समस्याएं:-

अधूरा सड़क व ब्रिज निर्माण:- शासकीय माध्यमिक शाला से दीपका की ओर जाने वाली रेल लाइन के बीच आवागमन हेतु अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण तो किया गया है, परंतु स्कूल से लेकर ब्रिज तक की सड़क का निर्माण कार्य इस्कॉन व राइट कंपनी द्वारा आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है।

नालियों का निर्माण शून्य:- वार्ड में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं किया गया है, जिससे वार्ड में गंदगी और जलजमाव की समस्या बनी हुई है।

दीपका बस्ती मार्ग पर उपेक्षा:- कृष्णा नगर को दीपका बस्ती से जोड़ने वाले रास्ते (ट्रांसफार्मर के समीप) स्थित दूसरे अंडर ब्रिज का कार्य भी पूरा हो गया है, लेकिन इस्कॉन व राइट कंपनी के द्वारा सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन बेहद कमखिम्भराम हो गया है ।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी जनसमस्याओं व मौलिक अधिकारों की पुर्नबहाली हेतु रेलवे प्रबंधन एवं संबंधित जिम्मेदार विभागों को जल्द ही एक ज्ञापन सौंपा जाएगा । वार्डवासियों ने शासन-प्रशासन और रेलवे प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस्कॉन व राइट कंपनी द्वारा कृष्णा नगर की मूलभूत व्यवस्थाओं को शीघ्र सुनिश्चित नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूरन विवश होना पड़ेगा।

‘स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चे ही सशक्त समाज का आधार’: आंगन मिलन समारोह में बोले मंत्री गजेन्द्र यादव; बांटे पोषण किट

दुर्ग (पाटन), 05 अक्टूबर 2026। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित ग्राम सेलुद में संस्कारों और व्यक्तिव निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं का प्रसन्न और सकारात्मक वातावरण में रहना बेहद जरूरी है। शासन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रहा है।

‘हर घर मुनगा’ का संदेश और **खिलौना दान** की अपील शिक्षा मंत्री ने आंगनबाड़ी समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रों को बच्चों के लिए अधिक आकर्षक और सुविधायुक्त बनाने



सालहेवारासालहेवारा में वीरांगना रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई

वनवासी विकास समिति के तत्वावधान में रानी दुर्गावती महाविद्यालय में हुआ आयोज

छुईखदान.सालहेवारा वनवासी विकास समिति सालहेवारा के तत्वावधान में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 502वीं जयंती रानी दुर्गावती महाविद्यालय, सालहेवारा में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में वीरांगना रानी दुर्गावती के अदम्य साहस, शौर्य, त्याग और मातृभूमि के प्रति उनके अमर समर्पण को नमन किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन डा. श्री रणजीत सिंह देशमुख ने किया। मुख्य अतिथि एवं प्रतिनिधि के रूप में श्री निजाम सिंह मंडावी, जिला पंचायत प्रतिनिधि सालहेवारा, श्री दशरथ पटेल, सरपंच सालहेवारा तथा श्री डीकेश मेरावी, पंच उपस्थित रहे। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के



कार्यकर्ता श्री रामश्याम, श्री देवकुमार साहू, श्री दिनेश धरम गढ़े एवं श्री गौकरण सोनवानी सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

समारोह में वक्ताओं ने वीरांगना रानी दुर्गावती के गौरवशाली जीवन, उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के लिए किए गए त्याग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया गया।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों ने वीरांगना रानी दुर्गावती के आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.....

दुर्ग में सुबह 4 बजे पुलिस की दबिश , 185 जवानों ने खंगाले संदिग्ध ठिकाने

अंचल वर्मा – दुर्ग, उत्ई। जनता के गोठ। दुर्ग पुलिस ने अपराध नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार सुबह जिले के तीनों पुलिस अनुभागों में एक साथ विशेष चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चले इस अभियान में दुर्ग, भिलाई नगर और छावनी अनुभाग के कुल 185 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस टीमों ने गुंडा-बदमाशों, निगरानी बदमाशों, वारंटियों और पहले से चिन्हित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध लोगों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान कई स्थानों से धारदार हथियार और अवैध शराब बरामद होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान फ़ार आरोपियों, गुंडा-बदमाशों, निगरानी बदमाशों और वारंटियों की तस्दीक की गई। टीमों ने संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों की जानकारी ली और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन किया। अभियान के तहत दूसरे क्षेत्रों से आकर संबंधित थाना क्षेत्रों में रहने वाले संदिग्ध और अनाधिकृत लोगों की भी जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच के साथ संदिग्ध गतिविधियों वाले स्थानों पर अचानक तलाशी भी ली। छावनी अनुभाग के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में देवार बस्ती और अटल आवास



में पुलिस टीमों ने घर-घर जाकर लोगों की तस्दीक की। तलाशी के दौरान कुछ स्थानों से धारदार हथियार और अवैध शराब मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। भिलाई नगर अनुभाग में फ़ीद नगर, डेरा बस्ती और सुपेला समेत अन्य चिन्हित क्षेत्रों में भी चेकिंग की गई। यहां पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के साथ वहां रहने वाले लोगों की जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया। मोहन नगर थाना क्षेत्र में आदतन बदमाश राहुल गाडा के घर के पास बिना नंबर की चक्ररू मोटरसाइकिल मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस वाहन के स्वामित्व और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर फ़िलहाल राहुल गाडा को इस वाहन के मामले में आरोपी घोषित नहीं किया गया है। वाहन के संबंध में सत्यापन की कार्रवाई जारी है। दुर्ग अनुभाग में उरला, अंबेडकर नगर, बांबे आवास, शंकर नगर, जवाहर नगर और ग्रीन चौक क्षेत्र में तलाशी और चेकिंग की गई। भिलाई नगर अनुभाग में फ़ीद नगर, डेरा बस्ती, सुपेला सहित अन्य चिन्हित इलाकों में पुलिस टीमें पहुंचीं। छावनी अनुभाग में खुर्सीपार को देवार बस्ती और अटल आवास में घर-घर जाकर लोगों की जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

हेतु जनसहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौने दान करने की अपील की, ताकि बच्चों को खेल-खेल में सीखने का बेहतर माहौल मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने पौष्टिक आहार एवं बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘हर घर मुनगा’ का संदेश दिया।

नशे से दूरी और मोबाइल के संतुलित उपयोग की सलाह कार्यक्रम के दौरान मंत्री यादव ने लोगों से पारिवारिक व सामाजिक आयोजनों में नशे से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही, मोबाइल के बढ़ते उपयोग पर चिंता

कोरबा जुड़ेगा हवाई सेवा से: रुमगरा एयरस्ट्रिप बनेगा कमर्शियल एयरपोर्ट, बढ़ेगी रनवे की लंबाई

कोरबा। औद्योगिक नगरी कोरबा में लंबे समय से चली आ रही हवाई सेवा की मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में कोरबा को शामिल किया गया है। इसके तहत रुमगरा एयरस्ट्रिप को विकसित कर कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में तैयार करने की योजना है। इसके लिए सिविल एविएशन की ओर से इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का प्रावधान किया गया है। जल्द ही तकनीकी टीम कोरबा पहुंचकर एयरस्ट्रिप का सर्वे करेगी।

प्रस्तावित योजना के तहत रुमगरा एयरस्ट्रिप का जामबहार की ओर विस्तार किया जाएगा। रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के साथ आवश्यक टर्मिनल भवन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तकनीकी और व्यावहारिक सर्वे के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। बताया गया है कि अगले कुछ महीनों में सर्वे और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।14 साल पुराना इंतजार खत्म होने की उम्मीदकोरबा में हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश नई नहीं है।

दिसंबर 2012 में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़

व्यक्त करते हुए उन्होंने अभिभावकों को स्वयं अनावश्यक मोबाइल उपयोग से बचने और बच्चों को इसके सीमित व सही इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने की सलाह दी।

कार्यक्रम में विभिन्न संस्कार हुए संपन्न समारोह के दौरान पुंसवन संस्कार, गोद भराई और शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत पाटन के अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक, सरपंच खिलेश मार्कण्डेय सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

एविएशन अकादमी के माध्यम से प्रदेश के पांच शहरों में एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी की थी, जिसमें कोरबा भी शामिल था। उस दौरान रुमगरा एयरस्ट्रिप से छह सीटर एयर टैक्सी का ट्रायल भी किया गया था। रायपुर के लिए किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी, लेकिन रनवे विस्तार और तकनीकी कारणों के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।इस बीच कोरबा से बाद में जुड़े अंबिकापुर में नियमित हवाई सेवा शुरू हो गई। अब उड़ान योजना में कोरबा के शामिल होने से शहरवासियों को एक बार फिर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। बिजली कंपनी की जमीन पर बनी है एयरस्ट्रिपरुमगरा एयरस्ट्रिप का निर्माण वर्ष 1980 के दशक में कोरबा पूर्व बिजली संयंत्र के निर्माण के दौरान अधिकारियों और विदेशी इंजीनियरों की आवाजाही के लिए किया गया था। उस समय यहां चार्टर्ड विमान उतरते थे। बाद में बिजली कंपनी के लिए इसका उपयोग सीमित हो गया।करीब दो दशक पहले बालको के विस्तार प्रोजेक्ट के दौरान बालको प्रबंधन ने एयरस्ट्रिप को अपने उपयोग के लिए लेना शुरू किया। वर्तमान में एयरस्ट्रिप के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी बालको के पास है।

धमधा में नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया, पॉक्सो केस दर्ज, DNA जांच की तैयारी



अंचल वर्मा – दुर्ग, उत्ई। जनता के गोठ।

दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है यहां कि एक नाबालिग किशोरी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है उसने एक नाबालिग युवक पर शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया है।

दुर्ग - धमधा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। नवजात और आरोपी युवक का छ्द्र टेस्ट कराया जाएगा।शिकायत मिलने के बाद धमधा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब नवजात और आरोपी बताए जा रहे युवक का छ्द्र परीक्षण कराने की तैयारी में है। ये सभी बातें फ़िलहाल शिकायत के आधार पर हैं और जांच जारी है।

शिकायत में बताया गया है कि करीब डेढ़ साल पहले इंटरनेट के जरिए किशोरी की पहचान

युवक से हुई थी। युवक का किशोरी के गांव में एक पड़ोसी के घर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात होने लगी और नजदीकियां बढ़ीं।

किशोरी का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर उससे संबंध बनाए। गर्भवती होने पर उसने युवक को बताया, तब युवक ने शादी की बात कही थी, ऐसा शिकायत में कहा गया है। किशोरी के मुताबिक, बाद में युवक ने परिवार के दबाव का हवाला देकर शादी से मना कर दिया। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किशोरी अपनी नानी के साथ रह रही थी। कुछ दिन पहले उसने नवजात को जन्म दिया। आरोप है कि जन्म की जानकारी मिलने पर युवक ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया।

युवक का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

छ्द्र जांच से क्या होगा? पुलिस नवजात और आरोपी बताए गए युवक का छ्द्र परीक्षण कराने की तैयारी में है। इसके जरिए दोनों के बीच जैविक संबंध की पुष्टि की

जशपुर के रणजीता स्टेडियम में रंगोली से उकेरी गई ‘डिजिटल इंडिया’ की तस्वीर: पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने दीप जलाकर दिया सशक्तिकरण का संदेश



जशपुर/रायपुर, 06 अक्टूबर 2026। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत जशपुर स्थित रणजीता स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन को एक विशाल एवं आकर्षक रंगोली के माध्यम से जीवंत रूप दिया गया। रंगों और रचनात्मकता के इस अनूठे संगम में डिजिटल तकनीक, ई-गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर

भारत की परिकल्पना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रवाल के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने रंगोली का अवलोकन कर इसके चारों ओर दीप प्रज्वलित किए।

अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच बना रहा है डिजिटल इंडिया: राजेश अग्रवाल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान ने देश में विकास और सुशासन को नई रफ्तार दी है। तकनीक के विस्तार से आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और अन्य शासकीय सेवाएं नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हुई हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी केवल तकनीकी



प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की सशक्त कड़ी है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है।

कलाकृति के जरिए दिया ‘कनेक्टेड इंडिया, स्ट्रॉनगर इंडिया’ का संदेश

स्टेडियम में बनाई गई विशाल रंगोली के कई महत्वपूर्ण थीम को शामिल किया गया:

- डिजिटल कनेक्टिविटी व ई-गवर्नेंस: रंगोली के मध्य में ‘डिजिटल इंडिया’ का संदेश अंकित था, जिसके साथ वाई-फ़ाई, क्लाउड तकनीक, मोबाइल और सरकारी भवनों के चित्रों द्वारा ई-गवर्नेंस तथा तकनीक

को शक्ति समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की सशक्त कड़ी है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है।

स्टेडियम में बनाई गई विशाल रंगोली के कई महत्वपूर्ण थीम को शामिल किया गया:

- डिजिटल कनेक्टिविटी व ई-गवर्नेंस: रंगोली के मध्य में ‘डिजिटल इंडिया’ का संदेश अंकित था, जिसके साथ वाई-फ़ाई, क्लाउड तकनीक, मोबाइल और सरकारी भवनों के चित्रों द्वारा ई-गवर्नेंस तथा तकनीक

